

# मालिकाना हक होते हुए भी कोटपूतली में लोगों को बेदखल किया जा रहा है

## ना पट्टों की वैल्यू ना रजिस्ट्री की, नगर परिषद ने अवैध कब्जे बता तोड़ डाले मकान, दुकान

कोटपूतली, 11 अगस्त (निर्सं)। कोटपूतली प्रशासन के समक्ष उनके द्वारा ही जारी किये गये पट्टों एवं रजिस्ट्रियों की कोई कीमत नहीं है, कोटपूतली प्रशासन इन सभी कागजातों को भी संभवतः अवैध व गैरकानूनी मान रहा है।

कोटपूतली में मास्टर प्लान 2011-2031 के अनुरूप कस्बे के मुख्य चौराहे से लेकर नगरपालिका तिराहा तक 80 फीट व पूर्वा सिनेमा से पुतली कट तक 60 फीट सड़कों के चौड़ाकरण को लेकर मुख्य चौराहे से लेकर अग्रसेन तिराहा, पुराने नगरपालिका भवन के सामने व नेहरू बाजार में जहाँ विगत 6 अगस्त को अल-सुबह करीब 5 बजे स्थानीय नगरपरिषद् प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी व पोकलेण्ड मशीनों द्वारा कई इमारतों, दुकानों को इकरतफा कार्रवाई ध्वस्त कर दिया। इस एक तरफा कार्रवाई से पीड़ित लोग हताश है क्योंकि मालिकाना हक होते हुए भी उन्हें सरकार द्वारा अपनी ही निजी प्रॉपर्टियों से बिना

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किये बेदखल किया जा रहा है।

गौरतलब है कि, गतवर्ष 14 व 15 दिसम्बर 2021 को नगरपालिका मण्डल कोटपूतली ने कुछ नागरिकों को नोटिस दिये कि चिन्हित जगह के दोनों तरफ के नागरिक अपने मकान, दुकान एवं अन्य निर्माणों को तीन दिवस के अन्दर हटा लेवें एवं अपने-अपने भूखण्ड से सम्बन्धित दस्तावेजात नगरपालिका मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा नोटिस में दी गई समा्यावधि के परचात उनके निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगा। इसी प्रकार इसी आशय का एक नोटिस 23 दिसम्बर 2021 को भी प्रेस विज्ञपित के माध्यम से दिया गया था।

लेकिन नगरपालिका कोटपूतली ने जिन व्यक्तियों को इस प्रकार के नोटिस प्रदत्त किये हैं उनमें से अधिकांश अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इन परिसरों पर पट्टे, लीज डीड के माध्यम से भूधारी एवं भूस्वामी है। परन्तु नगरपालिका कोटपूतली ने हठधर्मातिपूर्वक इन तथ्यों को नजर

- अब लोगों में इतना खौफ की खुद ही अपने घर, दुकान तोड़ रहे हैं।**

- परिषद आयुक्त ने वर्तमान में जारी पट्टों से लेकर खेतड़ी रियासत द्वारा जारी पट्टों तक के लिए कहा कि, ये गलत जारी हुए हैं।**

अंदाज किया एवं भूस्वामियों को अतिक्रमो की श्रेणी में माना है, जबकि नगरपालिका मण्डल कोटपूतली को कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इससे भयाकुल नागरिकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली, परन्तु दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय में 22 दिसम्बर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक शीतकालीन अवकाश पर था, परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सुनवाई हेतु अवकाशकालीन न्यायपीठ की तुरन्त स्थापना करते हुए 23 दिसम्बर को सुनवाई करते हुए नगरपालिका कोटपूतली की कार्यवाही पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई एवं शीतकालीन अवकाश के परचात सुनवाई के नोटिस की कार्यवाही के समीक्षा करें एवं प्रत्येक याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

तदुपरान्त उक्त 25

याचिकाकर्ताओं में से कुछ याचिका-कर्ताओं ने 7 जनवरी 2022 के निर्णय के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय की

### आंध्र को…

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
फोस्टर प्लस पार्टनर्स लिमिटेड को भुगतान नहीं करने के लिए नोटिस दिया। कम्पनी ने अमरावती को कोर कैपिटल क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाया था।

चीफ जस्टिस एन.वी. रमना की दो सदस्यीय बैंच, जिसमें जस्टिस कृष्ण मुरारी भी शामिल हैं, ने यू.के. की आर्टिकेटवट कम्पनी की याचिका स्वीकार की है जिन्होंने डिजाइन वर्क के बकाया भुगतान के लिए राज्य सरकार के साथ हुए विवाद में मध्यस्थता करने की मांग की है। अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी।

फोस्टर प्लस पार्टनर्स कम्पनी ने वर्ष 2018 में अमरावती के राजधानी क्षेत्र का मास्टर प्लान और इमारतों के डिजाइन बनाए थे। इन इमारतों में विधानसभा भवन, हाईकोर्ट परिसर व अन्य प्रशासनिक भवन शामिल हैं।

जानमोहन सरकार, जिसने मई 2019 में राज्य की सत्ता संभाली थी, ने अमरावती कैपिटल प्लान को रत्याग दिया और सभी काम रुकवा दिया साथ ही सभी भुगतान भी रुकवा दिए। तीन साल इंतजार करने के बाद कम्पनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने की इच्छा जताई है।

# ‘किश्त नहीं चुकाई तो जमा राशि पर कटौती जायज’

## जयपुर की स्थायी लोक अदालत ने आवासन मंडल के पक्ष में फैसला सुनाया

- लोक अदालत ने कहा कि, परिवारी ने कई रिमांडर भेजे जाने के बाद भी किश्त जमा नहीं करवाई थी, इसलिए आवासन मंडल जमा राशि से नियम अनुसार कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज लौटाए।**

इंदिरा गांधी आवासीय योजना में फ्लैट के लिए 2,96,000 रुपए पंजीकरण राशि जमा करवाकर आवेदन किया। बोर्ड ने फ्लैट

खण्डपीठ में अपील प्रस्तुत की। जिसपर 25 फरवरी 2022 को खण्ड पीठ ने एकल न्यायपीठ के निर्णय की विस्तृत व्याख्या करते हुए राजस्थान सरकार सहित अधिशाषी अधिकारी कोटपूतली एवं मण्डल अध्यक्ष कोटपूतली को यह निर्देश दिया कि, नगरपालिका कोटपूतली का नोटिस अभास्त एवं खण्डित किया जाता है। उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी नगर परिषद कोटपूतली के आयुक्त ने मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेन्द्र यादव की कार्यशैली के चलते 6 अगस्त को याचीगर्ण एवं नागरिकों के विधि सम्म्त निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

इसी बीच याचिगर्णों ने पुनः राजस्थान उच्च न्यायालय में राहत हेतु गुहार लगाई लेकिन इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के अवकाश होने के कारण 18 अगस्त को सुनवाई किया जाना निश्चित किया गया है।

इस कार्रवाई को लेकर लोगों का कहना है कि, जिन मकान और दुकानों को नगरपरिषद् प्रशासन ने अवैध मानते

# क्या ममता बनर्जी भी मायावती की…

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
यहां यह दिलाना जरूरी है कि यशवंत सिन्हाके नाम का प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस ने ही किया था तथा उसे आगे बढ़ाया था तथा उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पूरा समर्थन प्राप्त था।

2007 से 2012 तक, जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, उस समय सेवानिवृत्त आई.ए.एस. नेतराम उनके सबसे ज्यादा करीब माने जाते थे। वे पांच साल तक मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे थे।

इस बीच, जाति के दलित, नेतराम महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे कृषि विभाग में प्रधान सचिव रहे। इसके अलावा, वे एक्सआई, गात्रा, खाद्य तथा नागरिक उर्जा को गिनने के लिए एक इंतजार थे। सूत्रों का कहना है कि ममता तक यह संदेश पहुंचा दिया गया कि वे संयुक्त विपक्ष का हिस्सा बनने से दूर रहें, अन्यथा इसके परिणाम मायावती जैसे ही होंगे। टी.एम.सी. में कम से कम एक दर्जन ऐसे नेता हैं, जिनकी परिसम्पत्तियाँ, उनकी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में अनेक गुना ज्यादा हैं तथा इस मामले में एक याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका निबटारा शीघ्र ही कराया जा सकता है।

राष्ट्रपति चुनावों में, यशवंत सिन्हा से कह दिया गया था कि वे पश्चिमी बंगाल में अपना प्रचार नहीं करें तथा

- ममता बनर्जी के मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ मंत्री पार्श्वो चटर्जी का प्रकरण, इ-कम टैक्स के अभियान का पहला एपिसोड है। उसके बाद बीरभूम के तृणमूल के जिलाध्यक्ष अनुब्रत भण्डल व उनके एक खिलाफ बंगलादेश में मवेशी भेजने व बेचने के पुख्ता सबूत इकट्ठा करके सी.बी.आई. ने मंडल को गिरफ्तार कर लिया है तथा इनके साथ भी अरबों की सम्पति होने की चर्चा है।**

- क्या इन प्रकरणों ने ममताजी को प्र. मंत्री मोदी व भाजपा के प्रति नरम होने को बाध्य किया है?**

इसका कारण यह बताया गया था कि उनके राज्य में आने से तथा टी.एम.सी. द्वारा उनकी उन्मीदकारी का खुला समर्थन किये जाने से आदिवासी मतदाता पार्टी से दूर छिटक जायेंगे तथा सिन्हा कोलकाता नहीं गये।

उनके आमतौर से रहने वाले आक्रामक तैवरों में स्पष्ट बदलाव उपराष्ट्रपति चुनाव में दिखाई दिया, जब ममता ने कहा कि उनकी पार्टी मतदान से दूर रहेगी। खासतौर से उस स्थिति में, जब सत्तारूढ़ एन.डी.ए. के प्रत्याशी वही जगदीप धनखड़ थे, जिनके साथ, जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ममता की लड़ाई चलती रहती थी, उनका विपक्ष की प्रत्याशी मारिट अलवा का समर्थन न करने तथा मतदान तक से दूर रहने के निर्णय को क्या माना जाये। मतदान से दूर रहने का मतलब था-अप्रत्यक्ष रूप से

### उपराष्ट्रपति ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )
राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। शायद लेने से पहले सुबह धनखड़ राजघाट गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने द्वाीट किया राजघाट के पवित्र स्थित माहेील में पूज्य बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत की सेवा में तत्पर रहा ‘हम सब के लिए स्वयं को धन्य व प्रेरित महसूस किया। अपने वकालत कैरियर में धनखड़ सबसे युवा थे, जिन्हें 1987 राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। एक वर्ष बाद वे 1988 में वे राजस्थान बार काउन्सिल के सदस्य भी बने। उन्हे 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते हमेशा तल्ख रहे।

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

कहा कि अर्धव्यवस्था पर इनके “साइड इफैक्ट्स” का आकलन किया जाना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के वकील सिंघवी ने कहा, इम समझते हैं कि आपने गंभीर मुद्दा उठाया है। “फ्रीबी” शब्द का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। बैंक ने कहा “हम सजग हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं।” सिंघवी ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता का आवेदन है कि राजनैतिक पार्टियों को कोई भी वादा या दावा करने से प्रतिबंधित करने के लिए जिस तरीके से आदेश चाहा जा रहा हैं वह ना केवल मुश्किल है बल्कि अनुचित भी है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से समाजवादी व लोक कल्याणकारी पण्डेड को निराल फेकने से याचिकाकर्ता जातिवाद व सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति करेगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि याचिका, जिसमें से “मुफ्त सौगातों” हल्का सा ज़िक्र है, स्पष्ट रूप से आर्थिक

# ‘चुनाव के समय…

विकास के एक खास मॉडल के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही चाहती है। वे मुख्य रूप से समाजवादी कल्याणकारी साधनों पर होने वाले खर्च पर अंकुश लगाना चाहते हैं।’

विकसित देशों द्वारा अपनाई गई

कल्याणकारी योजना का हवाला देते हुए आपने कहा कि स्कैंडिनेवियन देशों के समाजवादी व लोक कल्याणकारी मॉडल के कारण इन देशों ने विकास के क्षेत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कमेटी का सुझाव सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया जिसमें केन्द्र सरकार का सचिव, राज्य सरकार का सचिव, विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, नीति आयोग, नेशनल टैक्स पेपर्स एसोसिएशन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा अगर मुफ्त सौगातों के लोक कल्याण मान लिया गया तो यह विनाशकारी होगा। पूर्व सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि गरीबों को मदद की आवश्यकता है।

बांदा, 11 अगस्त (वार्ता)। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गुरुवार को यमुना नदी में एक नाव डूबने की दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी और 17 लापता हैं, जबकि 15 अन्य को गोताखोरों ने सुरक्षित बचा लिया है। इस नाव में कुछ बहनें भी सवार थीं तो माइके अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही थीं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य तेज गति से चलाने के निर्देश दिये हैं। बांदा

### बार…

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

व मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इस संबंध में सभी बार एसोसिएशन को पत्र लिखा है। बीसीआर की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि, बार एसोसिएशन का हर सदस्य चुनाव से कम से कम दो दिन पहले शपथ पत्र पेश कर घोषणा करेगा कि उसने किसी अन्य बार एसोसिएशन में वोट नहीं डाला है। वहीं यदि यह घोषणा झूठी पाई गई तो ऐसे सदस्य को सदस्यता स्वतः ही तीन साल के लिए निलंबित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि बार एसोसिएशन ने निर्देशों की पालना नहीं की गई तो एसोसिएशन की संबद्धता को भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा बार काउन्सिल ने सभी बार एसोसिएशनसं को मतदाताओं की अपडेेट की गई सूची भी भेजने को कहा है। गौरतलब है कि, राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर व अन्य बनाम बीसीआर व अन्य मामले में बार एसोसिएशनों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। हाईकोर्ट के इन निर्देशों को कुछ संशोधनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखा था।

# बाराती बनकर आयकर विभाग ने 4 कंपनियों पर छापामारा

## किसी को भनक ना लगे इसलिए 260 अधिकारियों की टीम सजी-धजी 120 कारों में सवार होकर छापामारने पहुंची

मुंबई, 11 अगस्ता महाराष्ट्र के जानाना व छत्रपति शंभाजी महाराज नगर (औरंगाबाद) जिले में आयकर विभाग के अधिकारी बाराती बनकर पहुंचे। एक सप्ताह तक छापे की कार्रवाई की। शुरुआत तीन दिन तक स्थानीय पुलिस को भी भनक नहीं लगी। अब तक करीब आधा दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 390 करोड़ की संपति जब्त की जा चुकी है। आयकर सूत्रों के अनुसार, उन्हें स्टील कारोबार व फैक्ट्रियों के एक बड़े केंद्र जालना की चार कंपनियों छत्रपति शंभाजी महाराज नगर के व्यवसायी व प्रापटी डीलर द्वारा आयकर चोरी की भनक लगी थी। टोस सूचनाओं के आधार पर आयकर विभाग के 260 अधिकारियों की बड़ी टीम 120 कारों में छापामारने इन कंपनियों में जा धमकी। इन 120 कारों के काफिले में हर कार पर ‘दुल्हन हम ले जायेंगे’ का स्टिकर लगा था, ताकि देखने वालों के लगे कि कोई बारात जा रही है। तीन अगस्त को इनमें से एक टीम जालना के बाहरी इलाके में स्थित एक फार्म हाउस पर पहुंची और छापे की कार्रवाई शुरू की। जिन कंपनियों पर छापे मारे गए उनके

- इतना बड़ा काफिला देखकर किसी को शक ना हो जाये इसलिए सभी कारों के ऊपर “दुल्हन हम ले जायेंगे” के स्टिकर लगाये गये थे।**

- पूरी कार्रवाई इतने गुप्त तरीके से की गई कि, तीन दिन तक छापामारी चली, लेकिन स्थानीय पुलिस तक को भनक नहीं लगी।**

- इतनी बड़ी मात्रा में मिली नकद राशि को गिनने के लिए यह सारा रुपया स्थानीय स्टेट बैंक की शाखा में ले जाया गया, जहां इसे गिनने में कुल 13 घंटे लगे।**

नाम हैं-कालिका स्टील एलाय प्रालि, श्री राम स्टील, फाइनैसर विमल राज, एक डीलर प्रदीप बोरा व जालना का एक सहकारी बैंक। जिन स्टील कंपनियों पर छापे पड़े हैं, उनमें से एक की स्थापना 2003 में एवं दूसरी की 1985 में हुई थी। एक साथ इतने प्रतिष्ठानों पर छापेमारी के बावजूद स्थानीय पुलिस को तीन दिन तक इन छापों की भनक तक नहीं लग पाई। करीब आधा दर्जन प्रतिष्ठानों, उनके मालिकों व कर्मचारियों के विभिन्न टिकानों व उनके बैंक लाकरों से आयकर विभाग को 58 करोड़ रुपए नकद, 32

किलो सोना तथा कई बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद हुए हैं। इनकी कुल कीमत अब तक 390 करोड़ बताई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में मिली नकद राशि को गिनने के लिए एक सारा रुपया स्थानीय स्टेट बैंक की शाखा में ले जाया गया, जहां इसे गिनने में कुल 13 घंटे लगे। तीन अगस्त से शुरू हुई छापे की यह कार्रवाई आठ अगस्त तक चली।

## तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

मंडल के वकीलों ने सी.बी.आई. से कहा था कि उन्हें सी.बी.आई. के समक्ष उपस्थित होने के लिये 14 दिन का समय चाहिए, क्योंकि उन्हें फिट्टरुला का ऑपरेशन कराना है। एक बार तो राज्य के एस.एस.के.एम. अस्पताल के बदनम डॉक्टरों ने कह दिया था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की वस्तुतः कोई जरूरत नहीं है।

बंगाल की राजनीति ने प्लासी के युद्ध के दिनों से लेकर अभी तक सम्भवतः चोरी तथा चरित्रहीनता का ऐसा खुला प्रदर्शन एवं कारनामे नहीं देखे हैं। रोडनाथ, सत्तारूढ़, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य जनता की खुली लूट, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार के ऐसे उदाहरण

- मजे की बात यह है कि, अनुब्रत मंडल के कुछ नजदीकी साधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सी.बी.आई. की इस कार्यवाही का विरोध जताया। ये वो ही सब बातें करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, “यह केन्द्रीय सरकार की साजिश है तथा वो राज्य सरकार को कमजोर व बदनाम करना चाहती है। केन्द्रीय सरकार डरा कर तृणमूल नेताओं को राजनीति छोड़ने या भाजपा से जुड़ने का दबाव बना रही है।”**

पेश करते रहते हैं।

गिरफ्तारी से पहले, अनुब्रत मण्डल ने मवेशियों को तस्करी से बॉल्लादेश भेजने के मामले में सी.बी.आई. के समक्ष उपस्थित होने के 10 पूर्व सम्मनों की अनदेखी कर दी थी। उनके निजी सिन्वैरिटी गार्ड सैगल होसेन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि होसेन ने अनेकानेक सम्पत्तियों के देर लगा रखे हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रूपयों में है।

अनुब्रत के करीबी समर्थक तथा सहायक करीम खान एवं जिआउल हक भी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, एक पत्थर-व्यापारी, तुलु मण्डल के निवास पर भी छापामारा गया है। इन छापों तथा गिरफ्तारियों में 17 लाख नकद रूपये जब्त कर लिये गये,

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा कहती हैं कि, केन्द्र विपक्ष के नेताओं को धमकाने व भयभीत करने के लिए केन्द्रीय एजेंसिया का उपयोग कर रहा है तथा इन्हें फुसला रही है, विपक्ष को छोड़कर भाजपा के साथ आने के लिए। सत्तारूढ़ व्यवस्था भीतर तक भ्रष्ट साबित हो रही है तथा हर संभव अनियमितता बरत रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के सबसे करीबी लोग भी शामिल हैं।

प्रश्न यह है कि: कैबिनेट शैली की सरकार में, जो सामूहिक जिम्मेवारी पर आधारित है, क्या अब समय नहीं आया कि मुख्यमंत्री जिम्मेवारी लें और इस्तीफा दें। ऐसा हो जाता, बहुत पहले ऐसा हुआ होता, यदि राजनेताओं में ज़रा भी शर्म व आम सम्मान होता।

माईडन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथ्या, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 352144/79, जयपुर कार्यालय : सुधर्म एम.आई.रोड, जयपुर फोन: 272634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय : आयस मै न रोड आयड, उदयपुरा फोन: 2413092 , फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय - जौ 1/63, इन्डस्टीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौरा फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424
हिण्डोनीसटी कार्यालय -/- जी -1-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोनीसटी फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600
चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी